सच्चे लाल तिवारी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

6 अक्टूबर, 2004

[अरिजीत पासायत और सी. के. ठाकर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 300, अपवाद 4-की उपयोगिता-निर्णय किया, अपवाद 4 के आवेदन के लिए, यह स्थापित करने के अलावा कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी, यह दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है-तथ्यों पर, अपवाद का मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

आपराधिक कानूनः

बरी किए जाने के खिलाफ अपील-निर्णय किया-ऐसे मामलों में पालन किए जाने वाले सिद्धांत का पालन केवल तभी किया जाता है जब इसके लिए बाध्यकारी और ठोस कारण हों-तथ्यों पर, अभियुक्त को बरी करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है।

प्रमाणः

मौका गवाह-साक्ष्य-केवल एक स्वतंत्र गवाह को 'मौका गवाह' के रूप में वर्णित करके, यह निहित नहीं किया जा सकता है कि उसका साक्ष्य संदिग्ध है और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध है।

शब्द और वाक्यांशः ' अनुचित लाभ '-का अर्थ-व्याख्या

2001 की आपराधिक अपील संख्या 270 (ए-1) में अपीलार्थी और 2001 की आपराधिक अपील संख्या 271 (ए-2) में प्रतिवादी संख्या 1, दोनों भाइयों पर शिकायतकर्ता के दो बेटों की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि घटना की तारीख को, दोनों आरोपी अपनी बहन के बेटे 'पी' के साथ अपने कृषि क्षेत्र और शिकायतकर्ता के बीच की सीमांकन रेखा को तोड़ रहे थे। जब बाद वाला अपने दो बेटों के साथ वहाँ पहुँचा और आरोपी को सीमांकन में बाधा न डालने के लिए कहा, तो 'पी' ने एक पिस्तौल निकाली और उसे ए-1 को सौंप दिया और फिर 'पी' और ए-2 ने शिकायतकर्ता पक्ष को मारने का आह्वान किया। इसके बाद ए-1 ने शिकायतकर्ता के दो बेटों को गोली मार दी। शिकायतकर्ता (पीडब्लू. 1) और अन्य ग्रामीणों के अलावा, इस घटना को पीडब्लू. 2, एक स्वतंत्र गवाह ने देखा था। निचली अदालत ने ए-1 को आई. पी. सी. के तहत दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। ए-2 को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने ए-1 की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया

और ए. 2 को बरी कर दिया। पीड़ित ए-1 ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की; जबकि राज्य ने ए. 1 की सजा को कम करने और ए. 2 को बरी करने को चुनौती देते हुए अपील दायर की। अदालत ने ए-1 की सजा को कम करने के खिलाफ राज्य की अपील को खारिज कर दिया।

ए-1 के लिए यह तर्क दिया गया था कि पी. डब्ल्यू. 2 एक संयोग गवाह था और इस तरह, उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था; और यह कि, किसी भी घटना में, अभियोजन पक्ष के मामले ने केवल यह संकेत दिया कि घटना अचानक झगड़े के दौरान हुई थी और एस 300 के अपवाद 4 को देखते हुए, मामला आई. पी. सी. एस 302 के अंतर्गत नहीं आया था।

ए-2 के बरी होने के संबंध में, राज्य ने तर्क दिया कि स्वयं के साक्ष्य पर ए-1 को दोषी पाया गया था और ए-2 को बरी करने के लिए इसे खारिज करने का कोई प्रशंसनीय कारण नहीं बताया गया था।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. हत्या के मुकदमे में एक स्वतंत्र गवाह को 'संयोग गवाह' के रूप में वर्णित करके यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका सबूत संदिग्ध है और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध है। पी. डब्ल्यू. 2, जिसे अभियुक्त द्वारा 'संयोग गवाह' बताया गया है, एक स्वतंत्र गवाह था और गवाह को यह भी सुझाव नहीं दिया गया था कि उसकी किसी भी

अभियुक्त के प्रति कोई दुश्मनी थी। इसके अलावा, 'मौका गवाह' अभिव्यक्ति हमारे देश में काफी अनुपयुक्त है। (112-बी, सी, डी)

2. आई. पी. सी. की धारा 300 में अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि मृत्यु (ए) पूर्व-चिंतन के बिना, (बी) अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में; (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (डी) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त 'असम्यक लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'अनुचित लाभ'। तथ्यों पर, अपवाद 4 से एस300 का तत्काल मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। (113-सी, ई, एफ)

धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य, (2003) 5 सर्वोच्च 223, पर भरोसा किया।

3. जहां तक ए. 2 के बरी होने के खिलाफ राज्य द्वारा की गई अपील का संबंध है, ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का सिद्धांत केवल तभी है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और ठोस कारण हों। आपराधिक मामलों में न्याय के प्रशासन के जाल में जो सुनहरा धागा चलता है, वह यह है कि यदि मामले में पेश किए गए साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, एक

आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो वह दृष्टिकोण जो आरोपी के लिए अनुकूल है, अपनाया जाना चाहिए। तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने ए-2 द्वारा कथित प्रोत्साहन के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ निष्कर्ष निकालने के लिए पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य का विश्लेषण किया। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है। [113-जी, एच; 114-ए, ई; 114-सी)

भगवान सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 2 सुप्रीम 567; शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. (1973) एस. सी. 2622; रमेश बाबुलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, (1996) 4 सुप्रीम 167; जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2000) 3 सुप्रीम 320; राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2003) 7 सुप्रीम 152; पंजाब राज्य बनाम करनेल सिंह, (2003) 5 सुप्रीम 508; पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह और अन्य, (2003) सुप्रीम 17 और सुचंद पाल बनाम फनी पाल और अन्य, जे. टी. (2003) (9) एस. सी. 17, पर भरोसा किया गया।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 270/2001

1999 की आपराधिक अपील संख्या 621 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 27.9.2000 दिनांकित निर्णय और आदेश से

के साथ

आपराधिक अपील संख्या 271/2001

उत्तरदाताओं के लिए आर. के. सिंह और जितेंद्र कुमार भाटिया।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया

अरिजीत पासायत, जे.

ये दोनों अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले पर आधारित हैं। अपीलार्थी सच्चे लाल तिवारी (आपराधिक अपील सं 270/2001) और बच्चे लाल तिवारी (उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर 2001 की आपराधिक अपील में प्रतिवादी संख्या 1) को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। दोनों को दोषी पाया गया और तदनुसार दोषी ठहराया गया, जबकि पूर्व को मौत की सजा सुनाई गई, बाद वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपील दायर की गई। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने पूर्व के लिए सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और बाद वाले को बरी करने का निर्देश दिया।

दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन को बढ़ावा देने वाले तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता अछयबर मिश्रा (पीडब्लू-1) और दोनों अभियुक्त

उत्तर प्रदेश के समथ जिला वाराणसी के पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव लेडुपुर के निवासी हैं। गाँव के पूर्व और दक्षिण की ओर पुराने ईंट भट्टे के पास दोनों तरफ के कृषि क्षेत्र भी एक-दूसरे से सटे हुए हैं। शिकायतकर्ता अछयबर मिश्रा के क्षेत्र का जमीनी स्तर अपीलार्थियों के भूखंडों के स्तर से थोड़ा अधिक है। 3.11.1995 को सुबह लगभग 6.45 बजे, अभियुक्त व्यक्ति सच्चेलाल तिवारी और महाजन तिवारी के बेटे बच्चेलाल तिवारी और महाजन तिवारी के पोते पिंटू शिकायतकर्ता अच्छेबर मिश्रा और आरोपी के खेतों के बीच की सीमांकन रेखा (मेंड) को तोड़ रहे थे। शिकायतकर्ता अचयबर मिश्रा ने इसे देखा और वह अपने बेटों विजय शंकर मिश्रा और सुरेंद्र नाथ मिश्रा (जिन्हें इसके बाद उनके संबंधित नामों से 'मृतक' कहा जाता है) के साथ मैदान के पास पहुंचे और आरोपी से कहा कि वे मैदान की सीमांकन रेखा को न तोड़ें। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। महाजन तिवारी के पोते पिंटो ने एक पिस्तौल निकाली और उसे आरोपी सचचे लाल तिवारी को सौंप दिया और फिर पिंटो और बच्चे लाल तिवारी ने यह कहकर प्रोत्साहित किया कि शिकायतकर्ता पक्ष को मार दिया जाना चाहिए। इस पर आरोपी सच्चीलाल तिवारी ने मृतक विजय मिश्रा और मृतक सुरेंद्र पर पिस्तौल से गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों को पिस्तौल की गोली लग गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्रेम नाथ मिश्रा, रमाकांत मिश्रा (पीडब्लू-2) और गाँव के अन्य लोगों ने इस घटना को देखा और उसके बाद दोनों आरोपी और पिंटो शवों को छोड़कर घटना स्थल से भाग गए। शिकायतकर्ता अचाइबेट मिश्रा वाराणसी

जिले के पुलिस स्टेशन समथ गए और एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई।) वहाँ लगभग 8.15 बजे उस पर पुलिस स्टेशन में जी. डी. प्रविष्टि की गई और अपीलार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जाँच अधिकारी, एस. आई. श्री सीता राम चौधरी (पीडब्लू-6) घटना स्थल पर पहुँचे। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और साइट प्लान (प्रदर्श Ka-6)तैयार किया। इसके बाद उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और घटना स्थल से खून से सना मिट्टी का नमूना लिया और शवों के पंचायतनाम भी तैयार किए। शवों को जिला अस्पताल, वाराणसी भेजा गया जहां पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श केए-17 और केए-18 के माध्यम से 4.11.1995 को पोस्टमॉर्टम किया गया।। जाँच की आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। अभियुक्तों का बचाव यह था कि उन्हें पिछली शत्रुता और दुर्भावना के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों से पूछताछ की। अछयबर मिश्रा (पीडब्लू-1), रमाकांत मिश्रा (पीडब्लू-2) को चश्मदीद गवाह होने का दावा किया गया था। बचाव पक्ष ने यज्ञ नारायण मिश्रा (डी. डब्ल्यू.-1) और प्रेम नाथ मिश्रा (डी. डब्ल्यू.-2) से भी पूछताछ की। विद्वान निचली अदालत ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की जांच की, अभियोजन सिद्धांत पर विश्वास किया, अभियुक्तों को दोषी ठहराया और

उन्हें उपरोक्त के रूप में सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में सचचे लाल तिवारी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन उनका मानना था कि आजीवन कारावास उचित सजा है। इसने जहां तक आरोपी बच्चे लाल का संबंध है, सबूत को अपर्याप्त माना और तदनुसार बरी करने का निर्देश दिया।

यद्यपि उत्तर प्रदेश राज्य ने अभियुक्त सच्चे लाल के संबंध में सजा में परिवर्तन को चुनौती दी थी, लेकिन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। अपील बच्चे लाल को बरी करने तक सीमित है।

अभियुक्त के वकील श्री शिव पूजन सिंह ने कहा कि पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य अविश्वसनीय हैं। किसी भी स्थिति में, पीडब्लू-2 एक संयोग गवाह है जिसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था। भले ही अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, यह केवल यह दर्शाता है कि घटना अचानक झगड़े के दौरान हुई थी और इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 307 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

जवाब में राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य ने घटना का विस्तार से वर्णन किया है और इन्हें ठोस और विश्वसनीय माना गया है। कोई दुर्बलता नहीं देखी गई है और अपीलार्थी पी. डब्ल्यू.-2 को संयोग गवाह के रूप में वर्णित करने के अलावा कोई दुर्बलता नहीं दिखा पाया है। मामला स्पष्ट रूप से आई. पी. सी. की

धारा 302 के तहत आता है और आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। जिस क्रूर तरीके से दो व्यक्तियों की बेरहमी से हत्या की गई है, वह उक्त अपवाद को लागू नहीं करता है। दायर अपील के समर्थन में, यह प्रस्तुत किया गया कि स्वयं के साक्ष्य पर सचचे लाल को दोषी पाया गया है। बच्चे लाल को बरी करने के लिए इसे खारिज करने का कोई प्रशंसनीय कारण नहीं बताया गया है। जवाब में, श्री शिव पूजन सिंह ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य को अविश्वसनीय पाया हैं। फैसला बरी का होने के कारण और दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण होने के कारण, अपील खारिज किए जाने के योग्य है।

अभियुक्त की याचिका पर आते हुए कि पीडब्लू-2 'संयोग गवाह' था, जिसने यह नहीं बताया है कि वह घटना के कथित स्थान पर कैसे था, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त गवाह स्वतंत्र गवाह था। गवाह को यह भी सुझाव नहीं दिया गया था कि उसकी किसी भी आरोपी के प्रति कोई दुश्मनी है। हत्या के मुकदमे में एक स्वतंत्र गवाह को 'संयोग गवाह' के रूप में वर्णित करके यह निहित नहीं किया जा सकता है कि उसका साक्ष्य संदिग्ध है और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध है। हत्याएं गवाहों को पूर्व सूचना के साथ नहीं की जाती हैं; उनकी उपस्थिति का अनुरोध करते हुये। यदि हत्या किसी आवास में की जाती है, तो घर के निवासी स्वाभाविक गवाह होते हैं। यदि सड़क पर हत्या की जाती है, तो केवल

राहगीर ही गवाह होंगे। उनके साक्ष्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता है या इस आधार पर संदेह के साथ नहीं देखा जा सकता है कि वे केवल 'संयोग गवाह' हैं। 'संयोग गवाह' शब्द उन देशों से लिया गया है जहाँ हर आदमी के घर को उसका महल माना जाता है और हर किसी के पास कहीं और या किसी अन्य आदमी के महल में उसकी उपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह एक ऐसे देश में काफी अनुपयुक्त अभिव्यक्ति है जहां लोग कम औपचारिक और अधिक अनौपचारिक हैं, किसी भी मामले में अपनी उपस्थिति की व्याख्या करते हैं। नीचे की अदालतों ने पीडब्लू-2 के साक्ष्य को बहुत विस्तार से स्कैन किया है और इसे विश्वसनीय पाया है। हम अलग होने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए यह स्थापित करना होगा कि यह कार्य बिना पूर्व-चिंतन के किया गया था, अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में अपराधी ने अनुचित लाभ उठाए बिना और क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया था।

आई. पी. सी. की धारा 300 के चौथे अपवाद में अचानक लड़ाई में किए गए कार्यों को शामिल किया गया है। उक्त अपवाद अभियोजन के एक मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वधारणा का अभाव है। लेकिन, जबकि

अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की गर्मी है जो पुरुषों के शांत कारणों को प्रभावित करती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करेंगे। अपवाद 4 में उत्तेजना है जैसा कि अपवाद 1 में है; लेकिन की गई चोट उस उत्तेजना का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें भले ही कोई वारकिया गया हो, या विवाद की उत्पत्ति में या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें अपराध के संबंध में समान आधार पर रखता है। एक 'अचानक लड़ाई' का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर मार-पीट। तब की गई हत्या का स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए पता नहीं लगाया जा सकता है, न ही ऐसे मामलों में पूरे दोष को एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा था, तो अधिक उचित रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होगा। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक एक लड़ाई होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को कमोबेश दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने स्वयं के आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो यह उतना गंभीर मोड़ नहीं लेता जितना उसने लिया था। फिर आपसी उकसावा और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक पक्ष के लिए दोष के हिस्से को विभाजित करना मुश्किल होता है। अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) पूर्वकल्पना के बिना, (ख) अचानक लड़ाई में; (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर

या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। एक मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' आई. पी. सी. में परिभाषित नहीं है। लड़ाई करने में दो लोग लगते हैं। जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया है। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। किसी भी सामान्य नियम का उच्चारण करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का सवाल है और क्या झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'अनुपयुक्त लाभ'। धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य (2003) 5 सुप्रीम 223 में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। जब ऊपर बताए गए कानूनी सिद्धांतों में तथ्यात्मक परिदृश्य पर विचार किया जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 का मामले

के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। सच्चे लाल द्वारा दायर की गई अपील में कोई दम नहीं है। अब राज्य द्वारा दायर अपील आती है।

अपीलीय न्यायालय पर उन साक्ष्यों की समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन पर बरी करने का आदेश आधारित है। आम तौर पर, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि आरोपी के निर्दोष होने का अनुमान बरी होने से और मजबूत होता है। आपराधिक मामलों में न्याय के प्रशासन के जाल में जो सुनहरा धागा चलता है, वह यह है कि यदि मामले में पेश किए गए साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, एक आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो वह दृष्टिकोण जो आरोपी के लिए अनुकूल है, अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए। न्याय की विफलता जो दोषी के बरी होने से उत्पन्न हो सकती है, किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है। ऐसे मामले में जहां स्वीकार्य साक्ष्य की अनदेखी की जाती है, अपीलीय न्यायालय पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि वह उन साक्ष्य की पुनः सराहना करे जहां अभियुक्त को बरी कर दिया गया है, यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या किसी अभियुक्त ने वास्तव में कोई अपराध किया है या नहीं। [भगवान सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 2 सुप्रीम 567 देखें। बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत का पालन

केवल तभी किया जाना है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और ठोस कारण हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और प्रासंगिक और विश्वसनीय सामग्री को प्रक्रिया में अन्यायपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप का एक प्रभावी कारण है। इन पहलुओं को इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. (1973) एस. सी. 2622, रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, (1996) 4 सुप्रीम 167, जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2000) 3 सुप्रीम 320, राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2003) 7 सुप्रीम 152, पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह, (2003) 5 सुप्रीम 508, पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह और अन्य, (2003) 7 सुप्रीम 17 और सुचंद पाल बनाम फनी पाल और अन्रअन्य , जे. टी. (2003) 9 एससी 17 में उजागर किया गया था।

उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि पीडब्लू-2 के लिए प्रबोधन सुनना संभव नहीं होता क्योंकि वह दूर था। यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि उपदेश तेज आवाज में था। पीडब्लू-1 का साक्ष्य प्रबोधन के बारे में अस्पष्ट था। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है।

इस मामले को ध्यान में रखते हुए हम राज्य की अपील को खारिज करते हैं। अंत में, दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

आर. पी. अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।